(iv) *Need for setting up of a Caprolactum plant at Barauni.*

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय): उपाध्यक्ष महोदय, बरौनी बिहार में 200 करोड़ का कैप्रोलैक्टम प्लांट स्थापित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया, इसकी घोषणा भी कई बार हो चुकी है। निर्णय लेने के बाद अभी तक भारत सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। सुनने में आता है कि भारत सरकार अब इस योजना को स्थगित कर दूसरे प्रांत में कैप्रोलेक्टम प्लांट स्थापित करने का इरादा कर रही है।

बरौनी गंगा के किनारे है, आयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर खाद कारखाना, थर्मल पावर प्लांट एवं अन्य कई औद्योगिक कारखाने चतुर्दिक हैं। छोटे-बड़े अनेक उद्योग, एन्सीलरीज विकसित हो चुके हैं।

1981 में एक तकनीकी समिति ने भी बरौनी के कैप्रोलैक्टम प्लांट की अनुशंसा ही नहीं की, बल्कि प्रतिवेदन में लिखा है कि बरौनी ही सबसे उपयुक्त स्थान है, जहां इस प्लांट की स्थापना हो सकती है। इस नर्णय के कार्यान्वयन एवं सरकारी घोषणा में विलम्ब के कारण पूरे बिहार प्रांत की आम जनता में विशेषकर बरौनी बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में घोर असंतोष एवं निराशा व्याप्त हो गई है। इस संबंध में बिहार सरकार एवं बिहार के संसद सदस्यगण अनेकों स्मार-पत्र सरकार को दे चुके हैं। अतः भारत सरकार से निवेदन है कि बरौनी में कैप्रोलैक्टम प्लांट की स्थापना की दिशा में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे।

(v) *Need for development of transport facilities in Tarai area of Uttar Pradesh.*

श्रीयति ऊषा वर्मा (खीरी): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के कई जिलों में सड़क यातायात एवं परिवहन के साधनों का अत्यधिक अभाव है। यह क्षेत्र देश के सबसे अधिक पिछड़े ए भागों में से एक है। लखीमपुर खीरी जिला भी इसमें शामिल है, जहां सड़क परिवहन निगम का डिपो होते हुए भी परिवहन व्यवस्था दयनीय है। वास्तव में लखनऊ संभाग में जहां लाखों यात्रियों को लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में तराई इलाकों में जाना पड़ता है, बसों का घोर अभाव है। मोहम्मदी तहसील, जो बरेली क्षेत्र में आती है, और उसके आसपास का इलाका परिवहन और यातायात की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। रेल सेवा की शोचनीय हालत यात्रियों की परेशानियों को कई गुना बढ़ाती है। इससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है।

इस पिछड़े हुए इलाके के विकास और प्रगति की अत्यधिक आवश्यकता है, किन्तु परिवहन और यातायात के साधनों के अभाव में गरीब जनता के लाभ के छोटे-मोटे उद्योग भी नहीं खुल पाते। किसानों और व्यापारियों को अपना धंधा चलाना मुश्किल है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करती हूं कि इस क्षेत्र की गरीब जनता की भलाई के लिए यातायात और परिवहन व्यवस्था का तेजी से विकास करने का उत्तरप्रदेश शासन को निर्देश दिया जाये।

(vi) *Adequate compensation for land acquired for setting up a cantonment of Moradabad.*

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार मुरादाबाद में सैनिक छावनी (मिलिट्री कैन्टोनमेंट) स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके लिए आवश्यक जमीन का सर्वेक्षण, अधिग्रहण आदि की कार्यवाही भी चल रही है। इस में कोई संदेह नहीं कि सैनिक छावनी से स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और खुशहाली बढ़ेगी। इस से मुरादाबाद क्षेत्र को आधुनिक बनाने में भी मदद मिलेगी : किन्तु इस कार्य के लिए जिन व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है उन में मुआवजे के प्रश्न को लेकर असंतोष व्याप्त है। इन लोगों को समुचित मुआवजा एवम् अन्य स्थान पर जमीन दी जानी चाहिए। इनके पुनर्वास का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। जिन किसानों की जमीन ली गई है उन्हें अन्य स्थान पर खेती करने, लघु उद्योग लगाने और बिजली व सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए। अतः मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मुरादाबाद में सैनिक छावनी स्थापित करने के सिलसिले में जमीन लेने से प्रभावित किसानों को